भारतीय जनता पार्टी

आधारभूत ढांचा दृष्टिकोण
(INFRASTRUCTURE VISION)

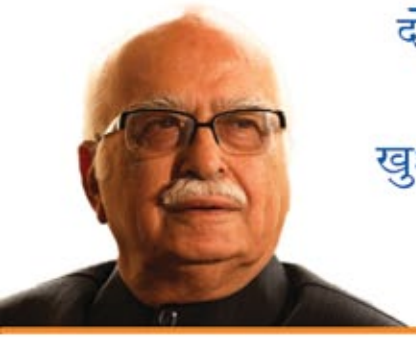

हमारे देश को सामाजिक तथा भौतिक,
दोनों तरह का ऐसा आधारभूत ढांचा चाहिए
जो 115 करोड़ भारतीयों की जिन्दगी में
खुशहाली और समृद्धि ला सके तथा बना सके

21 वीं सदी को भारत की सदी

सुशासन, विकास और सुरक्षा

भारतीय जनता पार्टी

क्षेत्र	प्रमुख वादे	प्रभाव
	सड़क जोड़ो परियोजना प्रत्येक गांव में जल संरक्षण सुविधाओं का निर्माण लघु सिंचाई पद्धतियों का व्यापक विस्तार	प्रत्येक खेत को जलस्रोतों से जोड़ा जाएगा पानी की हर बूंद से अधिक फसल
	पांच वर्षों में 1,20,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्रत्येक परिवार के लिए 30 केडब्ल्यूएच/माह बिजली और 6 किलो/माह कुकिंग गैस भारत को ग्रीन टेक्नालॉजी में अगुआ बनाना	प्रत्येक गांव को 24 घण्टे बिजली की सप्लाई प्रत्येक परिवार को एलपीजी पर्यावरण के अनुकूल इस्तेमाल
	स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण कॉरिडोरों को पूरा करना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पूरा करना राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन	सन् 2014 तक सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना सभी के लिए तेजी से यात्रा करने की सुविधा सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या को कम करके 45,000 लोगों की जिन्दगी बचाना
	फ्रेट कॉरिडोर चार बड़े शहरों और औद्योगिक केन्द्रों को जोड़ना 25 सबसे बड़े शहरों में मेट्रो रेल प्रणाली 100 बड़ी रेल परियोजनाओं को पूरा	किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी उत्पादों का सस्ती दरों पर वितरण तीव्र सार्वजनिक परिवहन
	भारतीय बन्दरगाहों का व्यापक विस्तार और आधुनिकीकरण अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास	बन्दरगाहों पर आसानी से पहुंच कार्गो को हटाने के समय में कमी लाना
	हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण हवाई अड्डों से बेहतर सम्पर्क	सस्ती और आरामदेह हवाई यात्रा हवाई अड्डों तक आसानी और सरलता से पहुंचना
	प्रत्येक गांव को केबल टीवी के मूल्य पर असीमित ब्रॉडबैंड सेवा भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को बढ़ावा बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र	ग्रामीण क्षेत्र में आईटी पर आधारित 1.2 करोड नौकरियां प्रत्येक भारतीय तक आईटी को पहुंचाना विदेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ को रोकना

आधारभूत संरचना के विकास हेतु दृष्टिकोण

आधारभूत संरचना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नींव होती है। अर्थव्यवस्था का पहिया कृषि और उद्योगों के लिए शक्ति, ऊर्जा, जल, लोगों के आवागमन और माल के परिवहन, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था के बिना संतोषजनक रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है और उत्पादन क्षमताओं का अपेक्षित स्तरों तक इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसके अलावा, इन भौतिक आधारभूत संरचनाओं के लिए राष्ट्र के ठोस आर्थिक विकास की आवश्यकता होती है और मानव विकास भी सामाजिक संरचना-शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, आवास, पेयजल तथा स्वच्छता, मनोरंजन, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और जनता के जरूरतमंद वर्गों की देखभाल पर निर्भर रहता है। पर्यावरण का संरक्षण भी इस आधारभूत संरचना की तीसरी कड़ी होती है जिसका महत्व जलवायु परिवर्तन के बारे में वैश्विक चिंताओं और वायु तथा जल की गुणवत्ता के बारे में स्थानीय चिंताओं में झलकता है।

कांग्रेस के कुशासन से आधारभूत संरचना में आई चिंताजनक कमी

भारत की मौजूदा भौतिक आधारभूत संरचनाओं तथा प्रस्तावित आवश्यकताओं और सही वास्तविकता के बीच के भारी अंतर को निम्नलिखित उदाहरणों से दर्शाया गया है :

क्षेत्र	भारत	तुलनात्मक उदाहरण
सड़कें	भारत के 3.3 मिलियन किलोमीटर के सड़क नेटवर्क में से केवल 2 प्रतिशत ही राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों में से केवल 8,000 किमी (12 प्रतिशत) ही दोहरे वाहन मार्ग हैं जो सभी चार लेन वाले नहीं हैं।	सन् 2007 के अंत तक चीन में चार या इससे अधिक लेन वाले लगभग 53,600 किमी लम्बे राजमार्ग थे।
रेलवे	चीन में इस समय 79,000 कि.मी. लम्बी रेललाइनें हैं जो सन् 2012 तक बढ़कर 1,10,000 कि.मी. हो जायेंगी जबकि भारत में उसी तारीख तक रेलवे नेटवर्क 2,000 कि.मी. से बढ़कर 65,300 कि.मी. हो जाएगा।	इसी वर्ष चीन 5,148 कि.मी. नई रेल लाइनों का निर्माण कार्य शुरू करेगा जोकि भारत के अगले 4 वर्षों में नई रेल लाइनों के लक्ष्य के दोगुने से अधिक है।

बंदरगाह	भारत में आयात कार्गो को निपटाने (क्लियरेंस) में औसतन 20 दिन लगते हैं:	सिंगापुर में इसके लिए तीन दिन लगते हैं।
विद्युत	सन् 2007 में भारत ने लगभग 7,000 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त क्षमता ही प्राप्त की।	चीन ने उसी वर्ष में 100,000 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त वृद्धि की।
दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारभूत ढांचा	भारत में 2.8 करोड़ पर्सनल कम्प्यूटर, 0.54 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता और 5.2 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं।	चीन में 16.2 करोड़ पर्सनल कम्प्यूटर, 8.5 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता और 29.8 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं।
शहरी आधारभूत ढांचा	दिल्ली में सन् 1997 में वाहन चलाने की गति औसतन 27 किमी प्रति घंटा थी जो वर्ष 2009 में घटकर 10 किमी प्रति घंटा रह गई है। कम सुविधाओं वाले शहरों में परिवहन प्रणाली इससे भी बदतर है। पैदलपथ और साइकिलों के लिए जगह ही समाप्त हो गई है।	चीन में भारत की अपेक्षा चार गुना वाहन होने के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या का 60 प्रतिशत है। (भारत में लगभग 1,30,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं।)
जल आपूर्ति	10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले 35 भारतीय शहरों में से किसी भी शहर में प्रतिदिन कुछ घंटों से अधिक के लिए जल वितरण नहीं होता है।	पेरिस जो प्रति नागरिक प्रतिदिन लगभग 100 लीटर जल सप्लाई करता है, २4 घंटे सातों दिन जल आपूर्ति करने में सक्षम है जबकि दिल्ली जैसे शहर जो प्रतिदिन प्रति नागरिक 300 लीटर जल सप्लाई करते हैं, ऐसा करने में असमर्थ हैं।
मलव्ययन	भारतीय शहरों में उत्पन्न जलमल (सीवेज) की केवल 13 प्रतिशत मात्रा का ही शोधन (ट्रिटमेंट) किया जाता है।	सन् 2007 के अंत तक चीन की मलव्ययन शोधन (ट्रिटमेंट) क्षमता प्रतिदिन 80 मिलियन टन तक पहुंच गई है और शहरी मलव्ययन शोधन की क्षमता 58 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
आवास	भारत की शहरी जनसंख्या अगले दो दशकों में दोगुनी होकर 57.5 करोड़ हो जाने का अनुमान है, जबकि भारत के शहरों में पहले से ही काफी अधिक जनसंख्या भरी पड़ी हैं। मुम्बई में 1.7 करोड़ लोग रहते हैं जिनमें से आधे लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।	
स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा	भारत के अस्पतालों में प्रति 1000 व्यक्तियों पर बिस्तरों की संख्या केवल 0.7 है जोकि विश्व औसत का पांचवा हिस्सा है।	अस्पतालों में बिस्तरों के मामले में विश्व औसत प्रति 1000 की जनसंख्या पर 3.96 है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण	भारत में केवल 5,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (IITs) हैं जिनमें भारत के विद्यमान कार्यबल का केवल 5 प्रतिशत ही कौशल प्रशिक्षण ले रहा है।	चीन में 5,00,000 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जहां कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कार्यबल की संख्या भारत से 100 गुना अधिक, कोरिया से 96 प्रतिशत अधिक, जर्मनी से 75 प्रतिशत अधिक और जापान के कार्यबल से 80 प्रतिशत अधिक है।

सन् 1980 में आधारभूत ढांचे के आंकड़ों के बारे में भारत और चीन की तुलना की गई थी तथापि, उपर्युक्त उदाहरणों से पता चलता है कि भारत पिछले तीन दशकों में चीन से काफी पिछड़ गया है। यह मुख्यतः इस आधारभूत ढांचे के अंतर के कारण है जिसने भारत की अपेक्षा चीन की अर्थव्यवस्था में काफी अधिक, तीव्र और स्थायी आधार पर वृद्धि की है।

यह चिंताजनक कमी मुख्यतः कांग्रेस जिसने स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत (केन्द्र और अनेक राज्यों) पर शासन किया है, के कुशासन और उसके द्वारा लम्बे समय तक इसकी उपेक्षा के कारण आई है।

यूपीए आधारभूत ढांचा विकास के लिए एक महाविपदा साबित हुई है।

इतिहास में यूपीए के कार्यकाल को पांच बर्बादी वाले वर्षों के रूप में रिकार्ड किया जाएगा। श्रीमती सोनिया गांधी और डा० मनमोहन सिंह की सरकार को इसकी अनेक विफलताओं और विश्वासघातों - अभूतपूर्व मूल्यवृद्धि, बड़े पैमाने पर नौकरियों की समाप्ति, हजारों की संख्या में कर्ज से लदे किसानों द्वारा आत्महत्याओं, सीमापार आंतकवाद से लड़ने में राजनीतिक इच्छा-शक्ति की कमी जिसकी वजह से काफी अधिक बेगुनाह लोगों की मौतें हुई हैं, के लिए याद रखा जाएगा। आधारभूत ढांचा विकास में इसकी विफलता कोई छोटी भूल नहीं है। यह कोई खाली राजनीतिक वाकपटुता भी नहीं है बल्कि ये तथ्य सरकार की रिपोर्टों में ही दिए गए हैं।

राजमार्ग : यूपीए शासन का निराशाजनक और भ्रष्टाचारयुक्त कार्य-निष्पादन राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) जोकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा शुरू की गई एक सबसे बड़ी तथा अधिक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा परियोजना है, में अधिक स्पष्ट रूप से झलकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की 3 नवम्बर, 2008 की 106वीं रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में कार्य-निष्पादन निराशाजनक रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) चरण-3 परियोजना में कुल 12,109 कि.मी. लम्बी सड़कों में से केवल 554 कि.मी. (5 प्रतिशत से भी कम) सड़कों का काम पूरा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) चरण-5 में 6500 कि.मी. सड़कों में से केवल 33 कि.मी. (0.05 प्रतिशत) सड़कों का कार्य ही पूरा किया गया है : **यदि पूरे एनएचडीपी कार्यक्रम को लिया जाए तो कुल 31,755 कि.मी. सड़कों में से केवल 9,165 कि.मी. (26 प्रतिशत) सड़कों का निर्माण कार्य ही पूरा किया गया है।** चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के स्वर्णिम चतुर्भुज घटक का अधिकांश कार्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन

(एनडीए) के शासनकाल में ही पूरा हो चुका था, इसका अर्थ है कि राजमार्ग निर्माण के कार्यक्रम के शेष कार्य की यूपीए के शासनकाल में भारी उपेक्षा हुई है।

एनएचडीपी स्थिति नवम्बर 2008	स्वर्णिम चतुर्भुज	एनएसईडब्ल्यू	एनएचडीपी3	एनएचडीपी5	एनएचडीपी
कुल लम्बाई कि.मी.	5846	7300	12109	6500	31755
कुल आज तक	5699	2879	554	33	9165
	-97.49%		-39.44%		26%
कार्यान्वयन के अधीन (कि.मी.)	147	3442	1521	997	6107
ठेका दिया जाना है		821	10034	5470	16325
वित्तीय आंबटन (करोड़ रू० में)					
ठेकों की लागत	3702	23880	2003	-975	28610
आज तक खर्च	28377	23698	6207	871	59155

यूपीए सरकार की उपेक्षा का एक दूसरा उदाहरण उच्च राजमार्ग परियोजना है। उच्च राजमार्गों के छठे पैकेज की निविदा 2008 में ऑफर की गई थी। 43 ठेकों में से किसी की भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। 17 ठेकों जिनकी निविदा बुलाई गई थी में से 6 ठेकों में एक निविदाकर्ता प्राप्त हुआ जिसके परिणामस्वरूप, इन 6 ठेकों में से किसी को भी मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के बिना अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। 11 ठेकों में से प्रत्येक ठेके में निविदा करने वालों को 35 प्रतिशत तक अधिक अनुदान प्राप्त हुए।

सन् 2004-05 में परियोजना पूरी होने की दर 81 प्रतिशत थी जो 2007-08 में घटकर 56 प्रतिशत रह गई। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं का ठेका देने की दर सन् 2005-06 में 70 प्रतिशत थी जोकि 2007-08 में 17 प्रतिशत तक गिर गई। उस पर कमाल यह कि इस अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सफलतापूर्वक अपना लगभग सारा धन व्यय कर रहा है! ऐसे विलम्बों के बारे में यूपीए का 'समाधान' वही घिसा-पिटा है : आधारभूत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी रखने हेतु एक और समिति का गठन किया गया था। इसके प्रमुख स्वयं प्रधानमंत्री होंगे! एक दूसरी समीक्षा जिसे योजना आयोग ने किया, के परिणाम सामने हैं – कि एनएचएआई अब परियोजना का ठेका देने में 20 महीने लगा रहा है जबकि 5 महीने में यह काम हो जाना चाहिए। **इसी एनएचएआई ने वाजपेयी सरकार के भूतल परिवहन मंत्री जनरल बी.सी.खंडूरी के निर्णायक और ईमानदार नेतृत्व में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के कार्य मौटे तौर पर निर्धारित समय और बजट में पूरे हुए।**

बंदरगाह : जनवरी 2004 और जनवरी 2008 के मध्य योजना आयोग और नौवहन मंत्रालय के

बीच खुला संघर्ष था कि किसका मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट (MCA) अपनाया जाए। योजना आयोग ने बार-बार प्रयास किया कि उसका अपना समझौता उस मंत्रालय पर थोपा जाए। अंततः जब 2008 में इसका समाधान निकला तब केवल एक बंदरगाह-एन्नोर-का ठेका दिया गया। इस पर भी मामला अदालत में पहुंच गया क्योंकि संवीक्षा के समय पर यह पता नहीं लग पाया कि दोनों निविदाकर्ताओं में हितों का टकराव था।

बिजली : स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) के अन्तर्गत 89,882 मेगावाट का क्रियान्वयन हो रहा है जोकि निजी क्षेत्र में चल रही कुल परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत है;

(क) इनमें से 80% ने अभी तक भूमि अधिग्रहित **नहीं** की है;
(ख) 57% मामलों में ईंधन सम्पर्क प्रदान **नहीं** किया गया है;
(ग) 90% मामलों में वित्तीय समाप्ति (Financial Closure) अभी होनी शेष है;
(घ) 86% को अभी तक ईपीसी देना शेष है; और
(ड) 91% मामलों में निर्माण अभी शुरू होना शेष है!

सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के एक वरिष्ठ रिसर्च फैलो पार्था मुखोपाध्याय ने आधारभूत ढांचा मोर्चे पर यूपीए सरकार की विफलता की सुस्पष्ट व्याख्या की है। अंतिम विश्लेषण में, **''आधारभूत ढांचे की प्रगति को अवरूद्ध करने के लिए इस सरकार को संभवतः दोष देना ठीक नहीं होगा क्योंकि इसने इस क्षेत्र में कार्य ही नहीं किया। अगली सरकार..... को इन कमियों को दूर करने के लिए अनुरूप कार्य करना होगा।''** (लाइव मिंट, 23 मार्च, 2009)

आधारभूत ढांचे के विकास को घटिया शासन से मुक्त कराना

यदि एनडीए को केन्द्र में अगली सरकार बनाने का जनादेश मिलता है तो वह भारत में आधारभूत ढांचे के अभाव को जल्दी से दूर करने के लिए कृत-संकल्प है।

अनुभव से यह पूरी तरह साबित हो गया है कि भारत में आधारभूत ढांचे के विकास में मुख्य बाधा धन नहीं बल्कि घटिया शासन है। आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में त्वरित कार्यान्वयन न होने की महत्वपूर्ण कड़ी का अभाव रहा है। यह खेद की बात है कि भारत में 250 से अधिक केन्द्रीय आधारभूत ढांचा संबंधी परियोजनाएं समय के लम्बे खिंच जाने और लागत में वृद्धि हो जाने का शिकार रही हैं। त्रुटिपूर्ण नीति तथा कानूनी ढांचा, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा निष्पादन के स्तर पर स्वायत्तता और जवाबदेही के अभाव ने परियोजना के कार्यान्वयन को पंगु बना दिया है। इसके कारण निर्माण और व्यवसायगत लागत में काफी अधिक बढ़ोतरी हो गई और भारत की प्रतियोगात्मकता कम हो गई।

भारत में आधारभूत ढांचे के परिदृश्य के बारे में सबसे मुखर सत्य यह है कि अभी भी 80 प्रतिशत आधारभूत ढांचे को सार्वजनिक व्यय द्वारा वित्त-पोषित किया जा रहा है। यह स्थिति परियोजनाओं के आयोजन, वित्त-पोषण और समयबद्ध निष्पादन में सरकार की सर्वोपरि भूमिका को रेखांकित करती है। इनमें वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) से चलाई जा रही हैं। भावी एनडीए सरकार इस जिम्मेदारी के प्रति जागरूक रहकर सार्वजनिक क्षेत्र में

परियोजना निष्पादन की दक्षता को बढ़ाने तथा प्राइवेट क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन को कारगर बनाने में साहसिक कदम उठाएगी।

हमारे विशिष्ट आश्वासन निम्न हैं :

1 **भारत का सार्वजनिक क्षेत्र हमारा राष्ट्रीय गौरव है।** दशकों से इसने आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में काफी अनुभव प्राप्त कर लिया है। दुर्भाग्यवश, संसाधनों में उपेक्षा, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, राजनीतिक तथा अधिकारीतंत्र के हस्तक्षेप, समान व्यवहार के अभाव और मानव संसाधन विकास की अनुचित नीति के कारण इसकी क्षमताएं दुर्बल हो गई हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) सरकार इन कमियों को दूर करेगा और सार्वजनिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनायेगा ताकि वह भारत में आधारभूत संरचना के विस्तार में अपना भरपूर योगदान दें सके।

2 राज्य उपयोगिताओं के कार्यान्वयन हेतु क्षमता निर्माण और आधारभूत संरचनाओं के परिचालन में अधिक आवश्यकता है। एनडीए सरकार आधारभूत ढांचा प्रबंधन के पांच राष्ट्रीय संस्थान खोलेगी ताकि वे केन्द्र, राज्य और म्युनिसिपल उपयोगिताओं के वरिष्ठ प्रबंधकों हेतु प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य कर सकें।

3 आधारभूत ढांचा परियोजनाएं विभिन्न स्तरों पर अनेक अनुमोदनों की वजह से पिछड़ती हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन एक राष्ट्रीय अधिकार-प्राप्त समिति की स्थापना करेगा जिसमें राज्य सरकारों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ताकि राष्ट्रीय तौर पर महत्वपूर्ण विद्युत तथा अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए शीघ्र अनुमोदन मिल सके।

4 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन और दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर समुचित सार्वजनिक क्षेत्र की वितरण एवं कार्यान्वयन इकाइयों जिनको अपेक्षित स्वायत्तता प्राप्त होगी, की स्थापना की जाएगी। इन इकाइयों को पूंजी प्राप्त करने और व्यावसायिक रूप से कार्य करने की अनुमति होगी।

5 भारत के निजी क्षेत्र में आकार और परियोजना कार्यान्वयन क्षमता की दृष्टि से काफी अधिक वृद्धि हुई है। सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी क्षेत्र का व्यापक विस्तार करते हुए निजी क्षेत्र के संसाधनों और क्षमताओं को पूर्ण समर्थन प्रदान करेगी।

6 उन नई, निष्ठावान स्वतंत्र कम्पनियों जो कोल इंडिया तथा एनएमडीसी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के विद्यमान उपक्रमों की पूरक होंगी, के माध्यम से भारत की आधारभूत संरचना संबंधी आवश्यकताओं को कायम रखने के लिए कोयला और लौह खनन में पर्याप्त निवेश किया जाएगा।

7 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन केन्द्र और राज्यों विशेषकर उन सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं जो विभिन्न स्तरों पर समस्याओं का सामना कर रही हैं, में स्पष्टता, पारदर्शिता तथा नीति एवं कानूनी ढांचे के समायोजन को पूरी तरह से बढ़ाएगा। विवाद समाधान तंत्र को अधिक गति प्रदान की जाएगी और उसे अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा।

8 राज्यों द्वारा अनिच्छा से सहयोग देने का एक कारण है–खनिज और दूसरे संसाधनों पर रॉयल्टी की कम दरें तथा राजमार्गों जैसी केन्द्रीय परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु फीस। ये दरें वास्तविक स्तरों तक बढ़ाई जाएंगी।

9 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) बाधामुक्त सिंगल विण्डो क्लियरेंस की शुरूआत करके प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। पर्यावरण सम्बन्धी अनुमोदन की पद्धति को उद्देश्यपरक, सरल एवं कारगर बनाया जाएगा। यह स्वीकार करते हुए कि कई परियोजनाओं को राज्य विशेष की क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, एनडीए यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ कार्य करेगा कि राज्य विशेष की विशिष्ट भावनाओं का सम्मान करते हुए सस्ती आधारभूत संरचना सृजित करने में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा जाए।

10 प्रतियोगितात्मक बोली लगवाकर संभावित बोली लगाने वालों को परियोजनाओं की आकर्षक सूची प्रदान की जाएगी। इसमें केन्द्रीय और राज्य प्राधिकारियों द्वारा दिए गए अनुमोदनों सहित सम्पूर्ण परियोजना ब्यौरा शामिल होगा।

11 उन परियोजनाओं जिनके लिए बहुविध अनेक अनुमोदनों, भूमि के अधिग्रहण, प्राकृतिक संसाधन और परिवहन सम्पर्कों आदि की जरूरत है, सरकार द्वारा 'शैल कम्पनियों' की स्थापना का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ताकि परियोजनाओं की प्रतियोगी बोली लगाने से पहले तैयारी की सभी कार्रवाई पूरी कर ली जाएं।

12 आधारभूत संरचना क्षेत्र के लिए विनियामक ढांचे को उन सभी बातों पर उचित ध्यान देने के बाद नया रूप दिया जाएगा जो विनियामक एजेंसियों और सम्बंधित मंत्रालयों के बीच संबंधों में स्पष्टता के अभाव या बहुलता के कारण और अलग–अलग क्षेत्रों पर ध्यान दिए बिना अधिभावी विनियम सिद्धांतों के अभाव में पैदा हो गए हैं जिनमें एक ठोस कानूनी ढांचा शामिल होगा जो उचित निष्पक्ष प्रतियोगिता के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए विनियामकों को क्षमता और सामर्थ्य प्रदान करेगा।

13 वर्तमान नीति ढांचे में सर्वाधिक प्रमुख दिक्कत है–भूमि और आधारभूत ढांचे की उपेक्षा जोकि छोटे और अनौपचारिक क्षेत्र के उत्पादकों तथा व्यवसायियों की जरूरत है। एनडीए सरकार इस कमी को दूर करने हेतु राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक अधिकार–सम्पन्न मिशन का गठन करेगी।

14 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण से किसानों के बीच भारी बेचैनी पैदा हो गई है। ऐसा प्रमुखतः इस कारण हुआ है कि यूपीए सरकार ने किसानों की कीमत पर भूमाफियों और बिचौलियों को मुनाफाखोरी करने की अनुमति प्रदान कर दी है। एनडीए इस समस्या का भूमि बैंक निगमों या न्यासों की स्थापना करके निदान करेगा जिनमें किसानों को भरपूर फायदे पहुंचाने के साथ उनमें शेयरधारी भी बनाया जाएगा।

15 परियोजना से प्रभावित लोगों के हितों की यह सुनिश्चित करके पूरी तरह से रक्षा की जाएगी कि उन्हें गारण्टीशुदा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के साथ–साथ आकर्षक मुआवजा भी प्राप्त हो।

प्रभावी तथा अनुकम्पापूर्ण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन हेतु एक कानून संसद के प्रथम सत्र में ही प्रस्तुत किया जाएगा।

16 चूंकि परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन तीव्र विकास की कुंजी है। इसलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) उन राज्यों और फर्मों को पुरस्कृत करने की एक प्रमुख योजना शुरू करेगा जो मुख्य आधारभूत परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

राष्ट्रीय महत्व की 100 परियोजनाएं

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रीय महत्व की 100 परियोजनाओं को चुनकर उनका समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। यहां पर क्षेत्रवार प्रमुख पहलों की निदर्शनात्मक सूची दी गई है :

जल

प्रत्येक घर के लिए स्वच्छ जल और हर खेत को पर्याप्त पानी

1 नदी जोड़ो परियोजना का तेजी से कार्यान्वयन करना। इसके अलावा, इस परियोजना से बार-बार आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटाने के अलावा भारत के ग्रामीण और शहरी इलाकों, दोनों को अनेक लाभ मिलेंगे।
2 प्रमुख सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं को पूरा करना।
3 देश के 6 लाख गांवों में से प्रत्येक गांव में कम से कम एक नई जल संरक्षण सुविधा (तालाब, रोकबांध आदि) का निर्माण करना तथा शहरी इलाकों में वर्षा जल के एकत्रीकरण को लोकप्रिय बनाना।
4 विद्यमान जल निकायों को प्रदूषणरहित करने, उनकी गाद निकालने और उनकी जलभराव क्षमता का विस्तार करने हेतु राष्ट्रीय मिशन।
5 'पानी की एक-एक बूंद से अधिक फसल उगाने' के लक्ष्य को बढ़ावा देने हेतु लघु सिंचाई पद्धतियों का व्यापक विस्तार करना।

ऊर्जा और बिजली

प्रत्येक घर, प्रत्येक खेत तथा प्रत्येक फैक्ट्री के लिए 24 घंटे सातों दिन सस्ती दरों पर बिजली

1 4,000 मेगावाट बिजली की क्षमता सहित अधिक उत्पादन वाले दस और अल्ट्रा मेगापावर प्रोजेक्ट (UMPPs) के माध्यम से पांच वर्षों में 1,20,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन। 100 दिनों के भीतर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) उन यूएमपीपी को पुनर्जीवित करेगा जो यूपीए शासन में लम्बित पड़े हुए हैं। तत्काल कैप्टिव पावर उत्पादन को जारी कर वर्तमान कमियों को पूरा किया जाएगा।
2 इसमें से पवन, सौर ऊर्जा और बायोमास पर आधारित परियोजनाओं जैसे गैर-परम्परागत

संसाधनों से 20% का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखना। ऊर्जा संरक्षण तथा हरित प्रौद्योगिकियों के अभिग्रहण हेतु राष्ट्रीय मिशन में काम करने के लिए विश्वभर के सर्वोत्तम बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करना ताकि भारत को ग्रीन एनर्जी में वैश्विक स्तर पर अगुआ बनाया जा सके। जापान, जर्मनी और अन्य देशों की अच्छी परम्पराओं को भी अपनाया जाएगा।

3 बिजली के पारेषण और संवितरण (T&D) की हानि को कम करने के लिए ट्रांसमिशन और संवितरण ढांचे का आधुनिकीकरण। 100 दिनों के भीतर एक ऐसा विश्वसनीय कार्यक्रम तैयार किया जाएगा जो बिजली ट्रांसमिशन और संवितरण क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कम से कम 1,00,000 करोड़ रूपये का निवेश उपलब्ध कराया जाएगा। संवितरण क्षेत्र में निवेश की कमी उच्चतम तकनीकी और व्यावसायिक हानियों का मुख्य कारण है।

4 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) राज्यों सरकारों के साथ मिलकर (क) पारेषण और संवितरण नेटवर्क का एक प्रभावी राष्ट्रीय बिजली ग्रिड बनाने; (ख) राज्य बिजली बोर्डों के घाटे को कम करने; (ग) लगातार उचित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने; (घ) बिजली चोरी रोकने के लिए काम करेगा और (ड) ''ओपन एक्सेस'' प्रणाली के माध्यम से वितरण स्तर पर प्रतियोगिता को बढ़ावा देना।

5 विफल राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (जिसमें यूपीए शासन के दौरान बीपीएल परिवारों की कवरेज मात्र 6%रही है) के स्थान पर 100 दिनों के भीतर नया कार्यक्रम शुरू करना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन का नया कार्यक्रम फ्रेंचाइज प्रदान करेगा जो पांच साल के भीतर सभी को इसमें शामिल करने की गारंटी देता है।

6 लगभग 60 करोड़ भारतीय बगैर बिजली के गुजारा करते हैं और लगभग 70 करोड़ भारतीय खाना पकाने की अपनी मूलभूत मानव आवश्यकता के लिए बायोमास पर निर्भर रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) प्रत्येक घर को प्रतिमाह 30 किलोवॉट बिजली तथा प्रतिमाह 6 किलोवॉट कुकिंग गैस उपलब्ध कराने का वादा करता है।

7 एलपीजी के लिए नए फ्रेंचाइजी कार्यक्रम की शुरूआत करना जिससे एक समयबद्ध-सीमा के भीतर सभी को इसकी उपलब्धता की गारंटी मिले।

8 समूचा ऊर्जा क्षेत्र बिगड़े ऊर्जा तंत्र से पीड़ित है। साथ ही हम बिजली पर कर और सब्सिडी भी देते हैं। इसलिए एनडीए ऊर्जा के सभी स्वरूपों में मूल्य और कराधान के सुधार हेतु एक पैकेज की घोषणा करेगा।

9 देश की जरूरत को पूरा करने हेतु कोयले का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को कोयला ब्लॉकों का आबंटन करने की नीति को प्रामाणिक ढंग से पुनर्भाषित करना।

10 कोयला, भारत की बिजली उत्पादन रणनीति का मुख्य आधार है और आगे बना रहेगा। यद्यपि कोयले को लेकर भारी पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) क्लीन कोल तकनीकों में भारी निवेश को प्रोत्साहित करेगा, ताकि भारत ''क्लीन कोल ग्रीन कोल'' के माध्यम से बिजली उत्पादन में एक अगुआ देश बन सकेगा।

11 एनडीए भारतीय बंदरगाहों से कोयले की 40 मिलियन टन ढुलाई के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर कम से कम 100 मिलियन टन करने का एक कार्यक्रम शुरू करेगा।

12 एनडीए ऐसे प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास भी शुरू करेगा जिनमें भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सड़कें

भारत के प्रत्येक शहर को जोड़ने वाले विश्व श्रेणी के राजमार्ग, भारत के प्रत्येक गांव को जोड़ने वाली पक्की सड़कें

1 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के सभी घटकों – स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण कॉरिडोरों और जिला राजमार्गों को पूरा करना। **स्वतंत्रता–प्राप्ति के पहले 50 वर्षों में भारत में 11 किलोमीटर प्रतिवर्ष की दर से राजमार्ग बनाए गए थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार (1998–2004) ने प्रतिदिन 11 किलोमीटर की दर से राजमार्गों का निर्माण किया! यूपीए शासन के दौरान यह दर गिरकर 5 किलोमीटर प्रति दर से भी कम रह गई।** राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की भावी सरकार 20 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से राजमार्गो का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाएगी।

2 प्रत्येक गांव को जोड़ने वाली पक्की सड़कों तथा सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों का निर्माण करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सन् 2014 से पहले पूरा करना।

3 सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या को आधा कम करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन का गठन करना।

रेलवे

प्रत्येक भारतीय के लिए रेलवे के सफर को आसान तथा आरामदायक बनाना।

1 दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई और कलकत्ता को जोड़ने वाले फ्रेट कॉरिडोर बनाना और इन्हें खनिज तथा औद्योगिक केन्द्रों से जोड़ना।

2 सभी लम्बित रेल नेटवर्क विस्तार परियोजनाओ ंको समयबद्ध तरीके से पूरा करना।

3 100 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना।

4 भारत के 25 सबसे बड़े शहरों में अर्बन मास ट्रांजिट (मेट्रो रेल) प्रणाली शुरू करना।

5 राष्ट्रीय रेल सुरक्षा मिशन को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना।

बन्दरगाह तथा नौवहन

भारतीय बंदरगाहों को विश्व के सर्वोत्तम बंदरगाहों की श्रेणी में लाना

1 भारतीय बंदरगाहों और नौवहन आधारभूत ढांचे का व्यापक विस्तार करने तथा उन्हें आधुनिक बनाने के लिए 'सागर माला' परियोजना शुरू करना।

2 कम से कम पांच महत्वपूर्ण मार्गों में अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास करना।

3 बंदरगाहों की प्रचालन क्षमता में सुधार लाना ताकि आयात कार्गों को साफ करने में लगने वाले औसत समय में कमी करके 20 दिनों से 5 दिन करना।

4 जहां कहीं संभव होगा, बंदरगाहों में पानी की गहराई को बढ़ाना ताकि वर्तमान क्षमता में वृद्धि की जा सके।

नागरिक उड्डयन

हवाई यात्रा को अधिक आसान, अधिक सुविधाजनक तथा अधिक सुरक्षित बनाना

1 प्रत्येक राज्य की राजधानी तथा महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र में हवाईअड्डा आधारभूत ढांचे को आधुनिक बनाना।
2 एक्सप्रेसवेज, एमआरटी तथा बसों की मदद से शहर से लेकर एयरपोर्ट के बीच आवागमन में सुधार लाना।

दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

सूचना, संचार और तकनीकी क्रांति को 'भारत' तक पहुंचाना

1 राष्ट्रीय डिजिटल राजमार्ग विकास परियोजना ताकि एक सशक्त दोष-रहित असीम क्षमता वाला राष्ट्रीय इंटरनेट आधार तैयार किया जा सके।
2 देश के हर छोर तक कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल सड़क योजना।
3 हर गांव के लिए केबल टीवी कनेक्शन के दामों पर असीमित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। (एमबीपीएस अपलोड तथा डाउनलोड सहित)
4 असीमित वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) टेलिफोन को अनुमति दी जाएगी।
5 मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 40 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करना; और मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या को बराबर करना।
6 ई-भाषा, भारतीय भाषाओं में आईटी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन।
7 ''सुशासन के लिए ई-गवर्नेंस'' हेतु अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में हम गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई ''ई-ग्राम विश्व ग्राम'' योजना को देशभर में लागू करेंगे। हरेक भारतीय नागरिक का एक बैंक खाता होगा; भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कल्याण निधियों को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
8 भारत में विश्व स्तर पर मुकाबला कर सकने वाले आईटी हार्डवेयर उद्योग का विकास करना जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सके।
9 बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र बनाने का काम तीन साल में पूरा करना।
10 ग्रामीण क्षेत्रों में 1.2 करोड़ आईटी पर आधारित नौकरियां देने की योजना बनाना।

ग्रामीण और कृषि पर आधारित बुनियादी ढांचा

हमारे गांवों में समृद्धि व खुशहाली लाना और रोजगार के अवसर मुहैया कराना

कृषि भारत की रीढ़ है। सतत् आधार पर भारत का आर्थिक विकास करने तथा 'इंडिया' और 'भारत' के बीच असमानता को कम करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास में व्यापक निवेश करेगा। इसके लिए हम ***पुरा*** (ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी सुविधाओं की व्यवस्था) की अवधारणा को मार्गदर्शक मानेंगे।

1 किसानों को 24 घण्टे सातों दिन बिजली की आपूर्ति करना (गुजरात में ज्योतिग्राम योजना के माध्यम से ऐसा पहले ही किया जा चुका है)।
2 हर गांव को पक्की और सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कें उपलब्ध कराना।
3 पीने के साफ पानी और सम्पूर्ण ग्रामीण सफाई की व्यवस्था करना।

4 कृषि पर आधारित बाजारों (मंडियों) के आधुनिकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाना जिसमें बिचौलियों को समाप्त करने के लिए कानूनी सुधार शामिल हैं ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके।

5 केबल टीवी के दामों पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट की व्यवस्था करना जिससे अन्य बातों के साथ-साथ, किसानों को फसलों, बाजारों का चयन करने और आधुनिक उत्पादन तकनीकें अपनाने जैसे सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

6 ग्रामीण इलाकों में अनाज बैंकों, शीत भण्डारों और कृषि प्रोसेंसिग ईकाइयों जैसे कृषि में मदद देने वाले आधारभूत ढांचे में व्यापक निवेश लगाना।

7 ग्रामीण आबादी के लिए पूर्ण वित्तीय समावेशन ताकि किसानों और ग्रामीण समाज के अन्य वर्गो की ऋण तथा बचत जरूरतों को औपचारिक बैंकिग प्रणाली से पूरा किया जा सकता है।

8 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में इस तरह से सुधार लाना जिससे यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में योगदान दे सके और भ्रष्टाचार खत्म हो सके।

9 शीघ्र खराब होने वाली कृषि उपज का निर्बाध निर्यात करने के लिए कार्गो केन्द्रों (Hubs) का विकास।

10 किसानों को कृषि उद्यमी बनाने हेतु कृषकों के लिए प्रशिक्षण एवं सहायता केन्द्र।

11 ग्रामीण आधारभूत ढांचे के बेहतर प्रबन्धन में चुने प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण।

'निफ्मा' की स्थापना और 100 श्रीधरनों का सशक्तिकरण :

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के स्पष्ट जनादेश के साथ 90 के दशक में स्थापित एफआईपीबी की तर्ज पर एक उच्च शक्ति-प्राप्त राष्ट्रीय आधारभूत ढांचा प्रोत्साहन और जांच एजेंसी (निफ्मा) गठित करेगा। 'निफ्मा' समय से पीछे चल रही अन्य परियोजनाओं में आई अड़चनों को भी हटाएगा। 'निफ्मा' में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की सर्वोत्तम प्रतिभाओं को शामिल किया जाएगा जिससे इसमें अभिनव सार्वजनिक और निजी भागीदारी की भावना प्रदर्शित होगी। यह राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं की प्रगति के बारे में तिमाही जानकारी राष्ट्र को देगा। 'निफ्मा' प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा।

राज्य सरकारों को इसी प्रकार की उच्च अधिकार-प्राप्त राज्य आधारभूत ढांचा प्रोत्साहन एवं जांच एजेंसी (सिफ्मा) स्थापना करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन यह मानता है कि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निर्णायक, परिणामकारी और प्रेरक नेतृत्व की जरूरत है। भारत के पास विशाल प्रबंधन प्रतिभा मौजूद है। दुर्भाग्यवश, हमारे प्रबंधकों को शायद ही स्वायत्तता और अपेक्षित अधिकार स्पष्ट जवाबदेही के साथ मिलते हैं ताकि वे अपना सही लोहा मनवा सकें। जब कभी एक सही प्रबंधक को सही परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सही अधिकार दिए जाते हैं तो हमें आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। दिल्ली मेट्रो के श्री ई.श्रीधरन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। लेकिन ऐसे और भी अनेक लोग हैं। **राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन ऐसे वातावरण का निर्माण करेगा जिसमें शीर्ष स्तर के प्रबंधकों का सशक्तिकरण किया जाएगा जो 100 श्रीधरनों को सामने ला सकें ताकि वे ''कुछ करके दिखा सकें।''**

सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल का बड़ी परियोजनाओं से आगे विस्तार करना

यद्यपि सरकार को आधारभूत ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य ही निभानी है परन्तु परियोजना के डिजाइन, वित्त–पोषण और कार्यान्वयन के नए–नए तरीके हाल के वर्षों में देखने को मिले हैं। सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल ने विशेष रूप से बड़ी आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं जैसे राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाईअड्डों इत्यादि के संदर्भ में अच्छा काम किया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) का मानना है कि अब समय आ गया है कि इसे ग्रामीण आधारभूत ढांचे (सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, शीत भण्डारगृहों और आधुनिक मण्डियों) की परियोजनाओं के साथ–साथ शहरी सेवाओं (बिजली आपूर्ति, कूड़ा–करकट निपटान, सफाई इत्यादि) में भी उपयोग करना चाहिए। इसके लिए व्यवहार्यता वित्त–पोषण वास्तविक आधार पर प्रदान किए जाने की जरूरत पड़ेगी। छोटे और मझौले स्थानीय उद्यमियों को सहायता मिलेगी ताकि वे अपनी भूमिका को परम्परागत ठेकेदार से बढ़ाकर आधुनिक और व्यापक प्रबंधकीय कुशलता के साथ परियोजना के विकास करने वाले (डेवलपर्स) बन सकें।

आधारभूत ढांचे के विकास हेतु वित्त–पोषण :

अगले पांच वर्षों के दौरान देश में आधारभूत ढांचा संबंधी घाटे में बड़ी कमी लाने के लिए अनुमानित 25,00,000 करोड़ रूपये अथवा 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की जरूरत है। यद्यपि इतनी धनराशि को जुटाना एक दुस्साध्य कार्य नजर आता है, फिर भी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) राष्ट्र को आश्वासन देता है कि वह इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेगा।

1 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन विदेशों के टैक्स हेवन्स में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से जमा भारतीय धन को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस धनराशि को हमारे देश के आधारभूत ढांचे के विकास में इस्तेमाल किया जाएगा।

2 अगले 5 वर्षों में आधारभूत ढांचे में सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation) को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10% तक बढ़ाया जाएगा।

3 भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार (जो इस समय 247.3 बिलियन अमेरीकी डॉलर है) का आधारभूत ढांचे के विकास के वित्तपोषण हेतु इस्तेमाल किया जाएगा।

4 2,00,000 करोड़ रूपये की चालू तथा नई परियोजनाओं हेतु इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड (IIFCL) के माध्यम से पुनः वित्तपोषण तथा ब्याज संबंधी लचीलेपन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें परियोजना की पूंजीगत लागत हेतु आईआईएफसीएल की कर्ज देने की सीमा को बढ़ाकर 20% से 40% किया जाएगा।

5 भारत को बड़ी आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए इक्विटी, विशेषकर बिग–टिकट इक्विटी की जरूरत है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक उपयुक्त कोष की स्थापना की संभाव्यता का पता लगाएगा जिसे सरकारी निधियों से मदद मिलेगी और यह निजी स्रोतों से भी धन जुटाएगा। इसके प्रबन्धन का स्वरूप व्यापक होगा जिसमें बोर्ड स्तर पर सरकारी प्रतिनिधित्व शामिल किया जाएगा। यह कोष अपनी निधियों में सह–निवेशकों के रूप में विश्वस्तर पर पेंशन तथा बीमा निधियों का भी इस्तेमाल करने की भी कोशिश करेगा।

6 राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए कम ब्याज दरों की व्यवस्था।
7 आधारभूत ढांचा तथा प्रमुख क्षेत्रों और समेकित टाउनशिप विकास परियोजनाओं को उधार देने वाली गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) को बाहर से वाणिज्यिक उधार लेने की सुविधा दी जाएगी।
8 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 50,000 करोड़ रूपये देकर उनकी पूंजीगत क्षमता बढ़ाई जाएगी।
9 राज्यों तथा शहरों में आधारभूत ढांचा संबंधी परियोजनाओं का वित्त-पोषण करने वाली वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को लिक्विडिटी सपोर्ट के रूप में लगभग 1,00,000 करोड़ रूपये प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रयोजन-साधन (Special Purpose Vehicle) सृजित किया जाएगा।
10 आधारभूत ढांचा सम्बन्धी उधार देने हेतु बैंकों के लिए ऋण की व्यवस्था करने और उधार देने के मानकों में ढील दी जाएगी।
11 आधारभूत ढांचा क्षेत्र को उधार देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के प्रति अलग व्यवहार करने की अनुमति दी जाएगी।
12 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन भारत में कारपोरेट बॉण्ड मार्केट का विकास करने के लिए आवश्यक विधायी तथा प्रशासनिक उपाय करेगा।

राष्ट्रीय समन्वित शहरी नवीनीकरण मिशन

भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। इस समय देश की 35 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या शहरी इलाकों में रह रही है। अगले दशक में इस आबादी के 50 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। 'अर्धशहरी' क्षेत्रों के उभरने से कई स्थानों पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विभाजन रेखा काफी छोटी होती जा रही है। दुर्भाग्यवश, क्रमिक कांग्रेस सरकारों द्वारा लम्बे समय तक उपेक्षा और कुशासन के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन के कार्यक्षेत्र को चार शहरी नवीनीकरण मिशनों में बांटेगा और उनका व्यापक विस्तार करेगा :

» **जवाहरलाल नेहरू मेट्रो नवीनीकरण मिशन** (10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले लगभग 40 शहरों के लिए)
» **सरदार वल्लभभाई पटेल जिला केन्द्र नवीनीकरण मिशन** (जवाहरलाल नेहरू मेट्रो नवीनीकरण मिशन में शामिल किए गए कस्बों को छोड़कर 600 से अधिक सभी जिला कस्बों के लिए)
» **नेताजी बोस तहसील कस्बा नवीनीकरण मिशन** (4000 से अधिक सभी तालुका कस्बों के लिए) और
» **पवित्र भारत तीर्थस्थान नवीनीकरण मिशन** (सभी धर्मों के तीर्थस्थानों के लिए)

उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत सामूहिक लक्ष्य होगा :

(क) 600 कस्बों की शत-प्रतिशत सड़कों को पक्का किया जाएगा;
(ख) प्रति व्यक्ति रोजना 90 लीटर अधिमानतः 24 घण्टे जल सप्लाई;
(ग) 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति;

(घ) शत-प्रतिशत भूमिगत जल निकासी तथा पर्यावरण के अनुकूल ठोस कचरा प्रबन्धन;
(ड) ठोस कचरा प्रबन्धन की आधुनिक प्रणालियों की शत-प्रतिशत कवरेज
(च) शत-प्रतिशत ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन;
(छ) शहरी जल निकायों और हरित जोनों का पुनर्विकास;
(ज) प्रत्येक जिले और तहसील केन्द्र में रेलवे और बस टर्मिनलों का आधुनिकीकरण तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉड) में आधुनिक प्रौद्योगिकियों वाली उत्कृष्ट परिवहन सुविधाओं का विकास;
(झ) प्रत्येक जिले और तहसील में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉड) में बाजार केन्द्रों, भण्डारण गृहों और गोदामों का आधुनिकीकरण;
(ण) सभी नागरिकों के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार;

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के व्यापक शहरी नवीनीकरण के दृष्टिकोण में निम्नलिखित मूलाधार और लाभ हैं : (1) स्थानीय गौरव के साथ राष्ट्रीय गौरव का प्रोत्साहन देना; (2) जिला और तहसील मुख्यालय 'भारत' और 'इंडिया' के केन्द्र-बिन्दु हैं। उन्हें अभिन्न राष्ट्रीय विकास के लिए एक आकर्षक मध्यस्थता बिन्दु बनाना; (3) जिला और तहसील मुख्यालय व्यापार और अर्थिक गतिविधि के स्वाभाविक केन्द्र होते हैं, जो आसपास के गांवों के लिए सामूहिक बाजारों के रूप में सेवाएं प्रदान करते हैं। इसलिए, उनके शहरी नवीनीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ेगा; (4) सामाजिक-आर्थिक विकास में भौगोलिक असमानता की समस्या को दूर किया जाएगा; (5) ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े शहरों विशेषकर राज्यों की राजधानियों की ओर लोगों का पलायन बढ़ता जा रहा है इससे शहरी आधारभूत ढांचे पर जनसंख्या का काफी दबाव पड़ता है। जिला मुख्यालयों के आधुनिकीकरण से राज्यों की राजधानियों की ओर लोगों के पलायन को रोककर तथा राजधानियों पर जनसंख्या के दबाव को कम करके ग्रामीण क्षेत्रों में जनसमाजों की रक्षा की जाएगी; (6) यह योजना जिला स्तरीय आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करेगी और यह विकासशील ग्रामीण भीतरी प्रदेशों में पहुंचने के लिए एक अवतरण मंच (लांचिग पैड) हो सकती है।

1 पांच वर्षों में कम से कम 15 भारतीय शहरों को विश्व स्तर के शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा जहां विश्व श्रेणी के हवाई अड्डे, कुशल जन परिवहन प्रणाली, उच्च कोटि का सामाजिक आधारभूत ढांचा, एक सक्रिय सांस्कृतिक जीवन, और सशक्त वैश्विक सम्पर्कों सहित आर्थिक विकास का एक सक्रिय माहौल होगा। कम से कम दस नए शहरों को आयोजना तथा आधारभूत ढांचे के भावी मानकों के आधार पर विकसित किया जाएगा।

2 भारत के महानगरीय केन्द्रों की आधारभूत ढांचे तथा अन्य शहरी नवीनीकरण आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। 20 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों में मेट्रो रेल परिवहन परियोजना शुरू की जाएंगी।

3 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन ''सभी के लिए मकान'' के अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन का गरीबों के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख आवासीय यूनिटों का निर्माण कराने का प्रस्ताव है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भारत में कम आय वाले लोगों के लिए 24 मिलियन आवास ईकाइयों की कमी का अनुमान लगाया गया है और आगे यह स्थिति और भी बुरी हो सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकारी गारंटियों के जरिए प्रभावी वित्तीय तंत्र बनाएगा और कर्ज की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए दैनिक बचत योजनाएं बनाएगा।

4 सभी बस्तियों के मानचित्रण (मैपिंग) का काम किया जाएगा और स्वामित्व दस्तावेज जारी किए

जायेंगे ताकि गरीब और मध्यम श्रेणी के लोग बैंकों से वित्त प्राप्त कर सकें और उसे अपने आवासों के सुधार पर निवेश कर सकें।

5 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन का झुग्गी-झोपड़ी सुधार तथा पुनर्वास का एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने और 'कच्चे मकानों को पक्के मकानों' में बदलने का भी प्रस्ताव है।

6 शहरी स्वच्छता को एक मिशन मॉड के रूप में लिया जाएगा।

नगरपालिका स्तर पर सुशासन

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन का मानना है कि नगरपालिका सुशासन और पंचायत सुशासन राष्ट्रीय स्तर पर सुशासन के महत्वपूर्ण अंग हैं। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से नगरपालिका सुशासन को एक मजबूत बनाए बगैर शहरी अपविकास को दूर नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्यवश, संविधान में 74वें संशोधन के प्रावधानों जिनमें शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण करने की अपेक्षा की गई है, को अभी तक अक्षरतः कार्यान्वित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन राज्य की राजधानियों से शहरी नगरपालिका निकायों को वास्तविक शक्तियों का हस्तांतरण करके इस कमी को दूर करेगा।

शुरू में, हम एक और संवैधानिक संशोधन प्रख्यापित करेंगे ताकि सभी शहरों में अनिवार्य रूप से एक प्रभावी और निर्वाचित मेयर-इन-कौंसिल सृजित करके त्रि-स्तरीय शासन को वास्तविक रूप में शक्तियां प्रदान की जा सकें। एक प्रभावी और निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष का सभी सरकारी कर्मियों और उनके शहरों तथा जिलों के लिए उत्तरदायी एजेंसियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण होगा।

पंचायत स्तर पर सुशासन

निचले स्तर पर सुशासन को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाएगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एनडीए निम्नलिखित कार्य करेगा :

1 पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को निधियों, कार्यों और कार्मिकों के बारे में प्रभावी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने हेतु कार्य करना। संविधान में संशोधन करके शक्तिओं का और विकेन्द्रीकरण किया जाएगा।

2 ग्राम सभा संस्था को मजबूत किया जाएगा ताकि वह विकास परियोजनाओं पर पूरी चर्चा कर सके, निधियों के आबंटन और खर्च की जांच कर सके तथा निर्वाचित एवं सरकारी कार्मिकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन कर सके।

वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई पथ-प्रदर्शक आधारभूत परियोजनाओं को यूपीए के निराशाजनक तथा भ्रष्टाचारयुक्त शासन ने ठप्प कर दिया

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वयन यूपीए शासन के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुआ

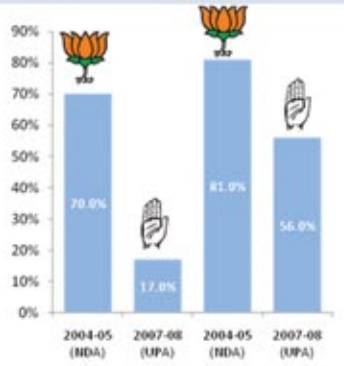

Project allocation rate

Project completion rate

यूपीए सरकार के घटिया शासन से आधारभूत ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ

-कांग्रेस पार्टी द्वारा लम्बे समय तक उपेक्षा और कुशासन
-विलम्ब होने से लागतों में 20 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई
-90,000 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की परियोजनाएं अक्षमता के कारण रूकी पड़ी हैं
-यूपीए की चाल से आधारभूत ढांचे में निजी निवेश हतोत्साहित हुआ
-गलत नीति और कानूनी अड़चनों के कारण भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आई
-भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप ने परियोजना कार्यान्वयन को पंगु बना दिया है
-समय-समय पर दिए गए 406 ठेके मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहले 50 वर्षों में भारत में 11 किलोमीटर प्रतिवर्ष की दर से 4/6 लेन वाले 556 किलोमीटर लम्बे राजमार्ग बनाए गए थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार (1998-2004) ने प्रतिदिन 11 किलोमीटर की दर से 4/6 लेन वाले 25,000 किलोमीटर लम्बे राजमार्गों का निर्माण किया!

तीव्र आधारभूत ढांचा विकास देश में तेजी से आर्थिक प्रगति लाने, बेरोजगारी को दूर करने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को पाटने, भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से व्यापक समृद्धि लाने तथा प्रत्येक नागरिक के लिए बेहतर जीवन-स्तर सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के आधारभूत ढांचे का युद्धस्तर पर विस्तार करने और उसे आधुनिक बनाने का हमारा पक्का वादा है। भारतीय जनता पार्टी ''बड़ा सोच'' सकती है और ''बड़ा ही कार्यान्वित'' करती है, यह विचार वाजपेयी सरकार की दो परियोजनाओं : राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से प्रदर्शित हो चुका है। हम नई दिल्ली में किसी भी पिछली सरकार की अपेक्षा अधिक महत्वाकांक्षी और परिणामोमुखी होंगे।

- लालकृष्ण आडवाणी

भारतीय जनता पार्टी, 11, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित

मुद्रक : एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ एफ काम्पलेक्स झण्डेवालान, नई दिल्ली -110055